Clearance for setting up a subsidiary of Rupert Murdoch's News Corporation in India

*358. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will thed Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has cleared the proposal of Rupert Murdoch's News Corporation to set up a wholly owned subsidiary in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The proposal of M/s. News Corporation, USA for setting up a wholly owned subsidiary in India to be engaged in development and sourcing of media software bringing in modern techniques and equipment, promotion and marketing of STAR TV, was recommended for consideration of Government by the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). However, Government have not cleared it.

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में खनिज उत्पादक इकाइयां

*359. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई खनिज उत्पादक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये इकाइयां किन-किन राज्यों में स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी इकाई में विदेशी निवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कुल रिपोर्टिंग खानों की संख्या 2927 है, जिसमें से 308 खानें सार्वजनिक क्षेत्र की तथा 2619 खानें निजी क्षेत्र की है। 2927 खानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये)

(ग) और (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने खनन/धातु कर्मीय क्षेत्र के लिए खान मंत्रालय द्वारा अनुशंसित 27 प्रस्तावों की निवेश पद्धति को अनुमोदित कर दिया है। तथापि पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) और खनन पट्टे (एमएल), खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किये जाते हैं। खनिज रियायत की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र केवल संबंधित राज्य सरकारों को दिये जाते है। फिर भी केवल खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-1 में सम्मिलित खनिजों के बारे में ही केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

विवरण

1995-96 के दौरान रिपोर्टिंग खानों की राज्यवार संख्या

राज्य	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
आंध्र प्रदेश	21	313	334
अरूणाचल प्रदेश	1	—	1
असम	1	2	3
बिहार	35	151	186
बम्बई हाई	—	—	—